

न्यायालय राजस्व अधिनियम अधिकांशी, जीएचए
 पीठासीन अधिकांशी श्री जयदेव शर्मा, आर.ए.एस.

2017RAAJU23RTA099 Bhanwarsingh etc Vs State of Rajasthan

1. अवसिंह पुत्र नरसिंह राजपुरोहित
2. विरवारसिंह पुत्र नरसिंह राजपुरोहित
3. मंगलसिंह पुत्र मंगलसिंह राजपुरोहित
4. नरसिंह पुत्र मंगलसिंह नरसिंह कायममर्कामान--
5. दलपतसिंह पुत्र मंगलसिंह राजपुरोहित
6. कौंसिंह पुत्र मूरजमलसिंह राजपुरोहित

----- अधिवापस

ब

ली

श

1. राजस्थान राज्य नरसिंह उपायुक्त अधिकांशी, जीएचए, जिला जीएचए
2. तहसीलदार, तहसील जीएचए, जिला जीएचए
3. बालावसिंह पुत्र तहसीलसिंह राजपुरोहित
4. भीमसिंह पुत्र अमरसिंह राजपुरोहित पुत्र भीमसिंह
5. नारायणसिंह पुत्र नरसिंह राजपुरोहित पुत्र भीमसिंह
6. मंगलसिंह पुत्र विरवारसिंह राजपुरोहित पुत्र बालावसिंह
7. कानसिंह पुत्र विरवारसिंह पुत्र बालावसिंह राजपुरोहित
8. अरसिंह पुत्र कौंसिंह पुत्र मकलसिंह राजपुरोहित

जिला पाली

----- सेप्टी.



अधीन अवगत विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं
 उपायुक्त अधिकांशी जीएचए दिनांक 03 अक्टूबर
 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 20/2017
 बालावसिंह बलाम अवसिंह आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री महेपाल राजपुरोहित, अधिवाप अधिवापस

~~Ms. Bhanwarsingh~~
 अधिकांशी

श्री कुमाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रे.पी. संख्या एक व दो श्री पूनाराम विखोई एवं श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रे.पी. संख्या

दीन से आठ

निर्णय

दिनांक : 21 नवंबर 2019
अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 20/2017 भंवरसिंह बलाम नसंवरसिंह व अन्य से पारित आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2017 के खिलाफ यह अपील अदातत हावा के समक्ष दिनांक 02 नवंबर 2017 को पेश की गयी है।

अपील के साथ अपीलान्टस की ओर से एक प्रशानापत्र भय

द्वारा अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा

अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा

अपील के साथ अपीलान्टस की ओर से एक प्रशानापत्र भय

द्वारा अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा

अपील के साथ अपीलान्टस की ओर से एक प्रशानापत्र भय

द्वारा अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा

अपील के साथ अपीलान्टस की ओर से एक प्रशानापत्र भय

द्वारा अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा

अपील के साथ अपीलान्टस की ओर से एक प्रशानापत्र भय

द्वारा अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा

अपील के साथ अपीलान्टस की ओर से एक प्रशानापत्र भय

द्वारा अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा

अपील के साथ अपीलान्टस की ओर से एक प्रशानापत्र भय

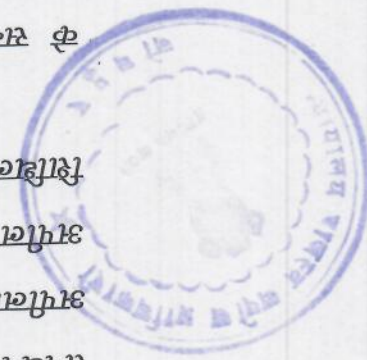
द्वारा अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा

अपील के साथ अपीलान्टस की ओर से एक प्रशानापत्र भय

द्वारा अपील नं. वि.नं. 3845 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा

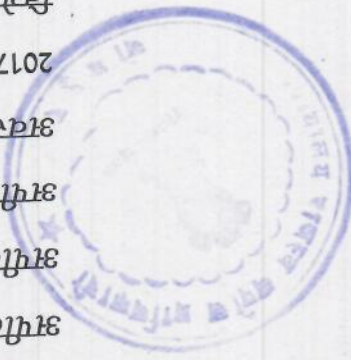
अपील के साथ अपीलान्टस की ओर से एक प्रशानापत्र भय

Handwritten signature and stamp at the top of the page.



वरुणसिंह का स्वतः ही अधीनस्थ न्यायालय को डाल ही जाता कि
 बाद प्रकरण की प्रभावों का अवलोकन ही नहीं किया, अत्याशा
 पारित किये जाने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सौंपे गए
 प्रमाणों पर प्रत्यक्ष करण का कोई अधिकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय
 वरुणसिंह में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि रजि. को सौंपे
 अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के मामले के तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय और अधिवक्ता
 उभयपक्ष के विरुद्ध अधिवक्तावृत्त की वरुणसिंह सौंपी गयी। विरुद्ध
 अक्टूबर 2017 के दिनांक आगोचर अधीनस्थ न्यायालय की गयी है।
 दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03
 2017 पारित कर मूल निर्णय एवं इसकी दिनांक 04 जुलाई 2016 खारिज कर
 अवसर प्रदान नहीं किया गया और अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 03 अक्टूबर
 अधीनस्थ न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जवाब या सुनवाई का
 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, मगर
 अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक नोटिस जारी कर दिये गये, नोटिस की पालना में
 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई नोटिस किये,
 किये जाने हेतु प्रेष किया गया, जिसमें वर्णित अधीनस्थ न्यायालय की प्रामाणिकता
 सौंपे गए प्रमाणों पर प्रत्यक्ष करण एवं इसकी दिनांक 04 जुलाई 2016 को अपारत
 बाद पूर्व: जुलाई 2017 में रजि. की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक
 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रमाणों पर विचारित किया गया। इसके
 दिनांक/नोटिस प्रेष खारिज किया जावे। तदनुसार दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को
 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी संपठित द्वारा 151 सीपीसी नरिसे
 प्रेष कर प्रमाणों के मध्य योजनीयता ही जा चुका है, अतः प्रमाणों पर
 समक्ष एक अन्य प्रमाणों पर विचारित प्रकिया सौंपी गयी 151 के तहत
 प्रमाणों पर प्रत्यक्ष करण संख्या 10 व 11 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के
 हुए भी प्रकरण संख्या 51/2016 दर्ज कर लिया गया। इसके बाद

अधीनस्थ न्यायालय
 अधीनस्थ न्यायालय



द्वारा न तो समय दिया गया और न ही अपीलापीन आदेश पारित किये

गाने के पूर्व उक्त दोनों प्रांजापनों का निस्तारण ही किया गया है।

अधिवक्ता-अपीलापट्टस का यह भी तर्क रहा है कि अपीलापीन आदेश

जिस प्रकार पारित किया गया है, वह विधिसंज्ञा नहीं है क्योंकि उससे

मूल वाद में पूर्ण: कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होती, अपितु मूल वाद में

पारित निर्णय, जिसके खिलाफ रिज्यू की कार्यवाही की गयी है, वह समाप्त

नहीं हो जाता है। रिज्यू उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि

मूल वाद में पक्षकार ही नहीं थे। अन्त में अधिवक्ता अपीलापट्टस ने

आर्गुमेंट्स अपील स्वीकार की जाकर अपीलापीन आदेश निस्तृत किये जाने

का निवेदन किया।

रेस्प. संख्या एक व दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण

के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार व्यापक निर्णय पारित किये जाने

का निवेदन किया।

जवाब में रेस्प. की ओर से विज्ञान अधिवक्ता ने कथन किया कि

रिज्यू पेश करने वाले बाद में प्रतिवादीवर्ग के विधिक उदारविहारी

और प्रकरण में हितवृद्ध व्यक्तित्व है, अतः उन्हें रिज्यू पेश करने का पूर्ण

अधिकार है। इसके विपरीत रिज्यू में पारित अपीलापीन आदेश के खिलाफ

आर्गुमेंट्स अपील अदालत द्वारा में संधारण योग्य ही नहीं है। राजस्थान

कार्यवाही अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत रिज्यू की कार्यवाही में

व्यापक निर्णय अर्थात् निर्णय को बदल सकता है। रिज्यू के आवश्यक शर्तें यह हैं

कि --

- कोई नया साक्ष्य पता चल
- देखने मात्र से पता चले कि प्रस्तावित आदेश

सही नहीं है

(Handwritten signature)
 अधिवक्ता-अपीलापट्टस

आगौर्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान

करावकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 03 अक्टूबर 2017 पर पत्र लिखा

गया है, वह स्पष्ट है, न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित मूलतः इस

अधिकरण के आदेश पर पत्र लिखा गया है कि मूल वाद में

प्रतिवादी न्यायालय से सहमत सभी पक्षों को है, प्रतिवादी न्यायालय सभी

पक्षों को संतुष्ट करने के लिए, आन भी उनके वारिस पक्षों को संतुष्ट

में ही निवास करते हैं, न्यायालय ने सभी मूल प्रतिवादी न्यायालय को

पक्षकार बना कर और झूठे निवास स्थान लिख कर डिक्री हासिल की जो

प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। अपने रिपोर्ट में प्रथम न्यायालय के साथ

डिक्री (मूल न्यायालय 02 जनवरी 2000), गोरखनाथ न्यायालय (मूल न्यायालय 02

जून 1987), अमरसिंह (मूल न्यायालय 18 अक्टूबर 2003), रामसिंह (मूल

न्यायालय 6 जनवरी 2001) व किशोरसिंह (मूल न्यायालय असफल) के मूल

प्रथम न्यायालय पक्ष किये गये। मूल वाद में यह सभी प्रतिवादी न्यायालय हैं और

मूल वाद में न्यायालय एवं डिक्री न्यायालय 04 जुलाई 2016 पर पत्र लिखे जाने के

पूर्व इन मूल प्रतिवादी न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय को पक्षकार नहीं

बनाया गया है। अतः निम्न किस्मि वाद-विवाद के यह तथ्य प्रथम दृष्टया

अधिकरण के अवलोकन मात्र से प्रकट हो जाते हैं कि मूल वाद के

निस्तारण में सारवाजब विधिक त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय आदेश

पर पत्र लिखे और मूल वाद में पत्र लिखे एवं डिक्री न्यायालय 04 जुलाई

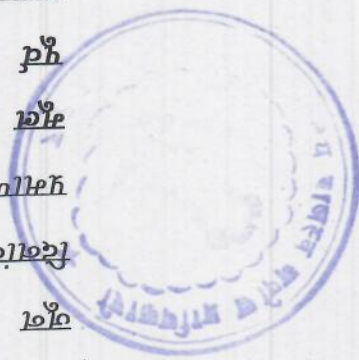
2016 पर पत्र लिखे तक कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

न्यायालय प्रथमतः अन्य 12 प्रतिवादी न्यायालय के मूल प्रथम न्यायालय पक्ष में

नहीं हुए। जो मूल प्रथम न्यायालय पक्ष में हुए, उनमें से एक प्रतिवादी की मूल

न्यायालय असफल होने से पहले में नहीं आ रही है। इस प्रकार 13

राजस्थान न्यायालय
जयपुर



पतिवादीवग के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इनका देहान्त किस

दिनांक को हुआ। जो प्रमाणपत्र पेश हुए, वे मात्र कोटिपतिया है, विधिवत

मूल प्रमाणपत्र अष्टीनरुष व्यायालय में पेश कर लियाआनुसार उन्हें प्रदर्श

करवाया जाना है। फिर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद यह निश्चित

किया जाना है कि सभी पतिवादीवग के देहान्त की जानकारी वादीवग को

थी अथवा नहीं, जानकारी थी तो कब से थी। जिस प्रकार मृतक

पतिवादीवग के वारिसान को राजस्व रिकार्ड बाबत कोई जानकारी नहीं

थी, क्या वादीवग को भी पतिवादीवग के बारे में, उनकी मृत्यु हो जाने

आदि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह भी एक बहस का बिन्दु है। इन

सभी बाबत मूल वाद में पुनः कार्यावाही आरम्भ की जाकर पक्षकारान की

साक्ष्य सुनवाई के बाद ही निश्चित किया जा सकता है। सीपीसी आदेश

47 (8) में स्पष्ट प्रावधान है कि "मंजूर किसे नये आवदन रजिस्टर में

बढाया जाना और फिर से सुनवाई के लिए आदेश" - यदि पुनर्विचार

का आवदन मंजूर कर लिया जाना है तो उसका दिपण रजिस्टर में किया

जायगा और व्यायालय मामले को वरुन्त फिर सुन सकता या फिर से

सुनवाई के बारे में ऐसा आदेश कर सकता जो वह ठीक समझे।

मगर अष्टीनरुष व्यायालय द्वारा अष्टीनरुष निरुपय में मात्र मूल

वाद में पतिव निरुपय व डिफी दिनांक 04 जुलाई 2016 को अपास्त किया

है, बकामा उपरोक्त आन्वदेश में इतिवत कार्यावाही बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं

किया है कि जिससे जाहिर है कि उक्त अष्टीनरुष व्यायालय द्वारा पतिव

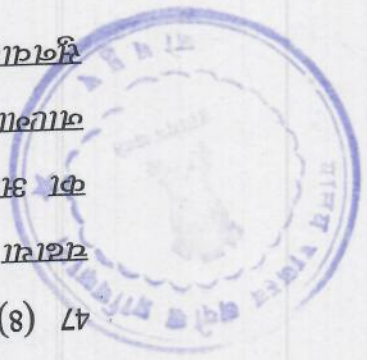
अष्टीनरुष निरुपय दिनांक 03 अक्टूबर 2017 अपने आप में अपूर्ण है।

अतः अपील अष्टीनरुष आशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और

अष्टीनरुष आदेश दिनांक 03 अक्टूबर 2017 इस प्रकार संशोधित किया

जाता है -

Handwritten signature and stamp at the top of the page.



03.10.2017 - अतः यशोपाल का यशोपाल स्टीकर

किया जाता है तथा राजस्व वाद संख्या 5/2014

भारसिंह बलाम सरदारसिंह अन्तोत द्वारा 88 व

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में

पारित निर्णय एवं इसकी त्रिांक 04 जुलाई 2016

अपारत किसे जाते हैं। मूल वाद प्रकरण पुनः दर्ज

किया जाकर अंतक प्रक्षारण के सभी विधिक

वारिस्थान को अभिलेख पर लिया जाकर उन्हें

सूनावाहूँ का समुचित अवसर देने हेतु कार्यवाही की

जाती है।”

निर्णय सुले व्याख्यान में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
(राज्यपाल कारकत)
29/11/19

